साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 7, अंक : 45 (प्रति बुधवार), इन्दौर 29 जून 2022 से 5 जुलाई 2022 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

गरीब देशों पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप गलत, G-7 को पीएम मोदी ने दिखाया आईना

नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के श्लॉस एल्मौ में जी-7 शिखर सम्मेलन (में भाग लिया. सम्मेलन शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की और फिर शिखर सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित किया. अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया के तमाम देशों से कहा कि यह एक भ्रांति है कि गरीब देश पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं.

बता दें कि जी-7 शिखर सम्मेलन का पहला सत्र जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य से संबंधित था. पीएम मोदी ने कहा कि भारत का 1000 से अधिक वर्षों का इतिहास इस भ्रांति या फिर दृष्टिकोण का पूरी तरह से खंडन करता है. भारत ने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में कभी भी कमी नहीं आने दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को आइना दिखाते हुए कहा कि भारत में विश्व की 17 प्रतिशत आबादी रहती है, लेकिन वैश्विक कार्बन इमिशन में हमारा योगदान सिर्फ 5 प्रतिशत का ही है. इसका मुख्य कारण हमारी लाइ स्टाइल है. पीए मोदी ने कहा कि ऊर्जा पर पहुंच सिर्फ अमीरों का ही प्रिविलेज नहीं होना चाहिए बल्कि एक गरीब परिवार का भी ऊर्जा पर बराबर का हक है. पीएम ने कहा कि हमने भारत में घर घर में एलईडी बल्ब और क्लीन कुकिंग गैस को पहुंचाया है और यह दिखाया कि गरीबों के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करते हुए कई मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन से बचा जा सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जलवायु के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वह हमारे परफॉर्मेंस से ही स्पष्ट है. पीएम ने कहा कि हमने 40 प्रतिशत ऊर्जा कैपेसिटी का लक्ष्य 9 साल पहले ही पा लिया था. इसके साथ ही पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथनॉल ब्लेंडिग का लक्ष्य हमने समय से पांच महीने पहले ही प्राप्त कर

लिया. पीएम मोदी ने ग्रुप ऑफ सेवेन को बताया कि भारत में विश्व का पहला पूरी तरह सोलर पावर संचालित एयरपोर्ट है. भारत का विशाल रेलवे सिस्टम इसी दशक में नेट जीरो के टॉरगेट को पा लेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आशा है कि त्र-7 के समृद्ध देश भारत के प्रयत्नों को समर्थन देंगे.

1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, पर्यावरण मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली। पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए सरकार कई स्तर पर प्रयास कर रही है। 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक कैरी बैग पर पहले ही प्रतिबंध लगाया गया है। एक बार फिर सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है।

सरकार द्वारा लगाया गया प्लास्टिक पर प्रतिबंध ऐसी चीजों पर लागू होगा जो कम इस्तेमाल होते हैं या एक बार इस्तेमाल होती हैं। क्योंकि इनसे कचरा ज्यादा फैलता है। जिसमें प्लास्टिक के कप गिलास कटोरी इत्यादि शामिल है। सिंगल यूज प्लास्टिक जिस पर 1 जुलाई से सरकार ने बैन लगा दीया है। सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसी वस्तुओं को कहा गया है जो प्लास्टिक से बनी होती हैं और एक बार से ज्यादा उनका उपयोग नहीं होता। ऐसी प्लास्टिक की वस्तुएं कचरा ज्यादा फैलाते हैं। जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। प्लास्टिक से पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। जानकारी के अनुसार 1 जुलाई से पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉक, वितरण, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताया गया है कि प्लास्टिक की वह डंडी जिसका उपयोग लॉलीपॉप में किया जाता है उसे भी प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही प्लास्टिक के कप, गिलास, चम्मच, कांटे, चाकू, इयरबड तथा प्लास्टिक क्या पीवीसी से बने 100 माइक्रोन वाले बैनर पर प्रतिबंध लगाया गया है।

दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कार्बन भंडारण प्रणाली पर असर डाल रहा है जलवायु परिवर्तन- अध्ययन

मैंग्रोव मैंग्रोव वन हमारी धरती के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ और झाड़ियां पर्याप्त मात्रा में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को अवशोषित करते हैं। मैंग्रोव समुद्र के नजदीक रहने वाले समुदायों को बढ़ते समुद्र के स्तर से बचाने में मदद करते हैं।

ये तटीय इलाकों में उगने वाले वन दुनिया में दूसरे सबसे अधिक कार्बन समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र हैं। जो एक हेक्टेयर में 1,000 टन से अधिक कार्बन जमा करने में सक्षम हैं, जो कि एक फुटबॉल के मैदान के आकार के बराबर है। वे हवा से रासायनिक तत्व को अवशोषित कर पत्तियों, शाखाओं और जड़ों में जमा करके ऐसा करते हैं। लेकिन इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों के नुकसान को रोकने के लिए पर्यावरणीय प्रयासों के बावजूद, वे अभी भी खतरे में हैं। पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय द्वारा और अनुसंधान संगठन ऑपरेशन वालेसिया द्वारा किए गए एक नए अध्ययन से पता चला है कि बड़े लकड़ी के मलबे में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ 2) से संग्रहीत कार्बन को जीवों द्वारा कैसे संसाधित किया जाता है। निष्कर्ष बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन इस %ब्लू कार्बन% प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया के वाकाटोबी नेशनल पार्क में चार मैंग्रोव जंगलों में लकड़ी का बड़ा मलबा (एलडब्ल्यूडी) का विश्लेषण किया, जिसमें अलग-अलग इंटरटाइडल ज़ोन हैं। प्रत्येक सर्वेक्षण क्षेत्र में 8 खंड थे - इनमें से हर एक कार्बन प्रसंस्करण के अपने तरीके का खुलासा करते हैं । पारिस्थितिकी तंत्र की ऊपरी स्तर की पहुंच वाली भूमि के करीब, जो कि आमतौर पर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाने वाले जीव इन पड़ी हुई लकड़ी को नष्ट कर देते हैं। इन जीवों में कवक, बीटल लार्वा और दीमक शामिल हैं। आगे समुद्र की ओर, लकड़ी के बड़े मलबे को कैल्शियम कार्बोनेट के गोले के साथ कृमि जैसे क्लैम द्वारा और अधिक तेजी से नष्ट किया जा रहा है, जिसे शिपवॉर्म के रूप में जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन मैंग्रोव वन में स्थिर कार्बन क्षरण की नाजुक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले तो समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन चक्र ज्वार की ऊंचाई से चलता है। दूसरा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण समुद्र की अम्लता में वृद्धि हो रही है, जो निचले स्तर पर लकड़ी को नष्ट करने वाले समुद्री जीवों को मार सकता है। प्रमुख अध्ययनकर्ता और यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के डॉ. इयान हेंडी ने कहा कि ये आंकड़े लकड़ी को बायोडिग्रेड करने वाले जीवों और सड़ती हुई मैंग्रोव की लकड़ी के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करते हैं। मैंग्रोव वन जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा जंगलों में पड़ी हुई लकड़ी के सड़ने से ऊपर के कार्बन चक्र बदल जाएंगे, जिसका प्रभाव मैंग्रोव कार्बन भंडारण पर पड़ सकता है। डॉ. हेंडी और उनकी टीम अब मेक्सिको में बड़े पैमाने पर मैंग्रोव वन की बहाली करने की तैयारी कर रही है। सह-अध्ययनकर्ता डॉ साइमन क्रैग ने कहा टीम का लक्ष्य अब इस अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग दुनिया भर में मैंग्रोव वनों की बड़े पैमाने पर बहाली के लिए मार्गदर्शन करना है। यह अध्ययन फ्रंटियर्स इन फॉरेस्ट एंड ग्लोबल चेंज में प्रकाशित हुआ है।

नशा मुक्त गाँव को प्रदान किया जाएगा 2 लाख रूपए का पुरस्कार- मुख्यमंत्री श्री चौहान

बेटी फ्रेंडली हो हमारी पंचायतें

भोपाल मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समरस पंचायतों में नशा मुक्ति का अभियान चलाया जाए। नशा मुक्त गाँव को विशेष रूप से 2 लाख रूपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ग्राम को नशा मुक्त बनाने के लिए आपसी बातचीत और विभिन्न प्रेरणास्पद गतिविधियों से वातावरण निर्मित किया जाए। यह सुनिश्चित करें कि हमारी पंचायतें ÷बेटी फ्रेंडली÷ हों। समरस पंचायतों सहित सभी पंचायतों में बेटियों का मान, सम्मान और इज्जत बढ़े। बेटा-बेटी को बराबर माना जाए। माँ, बहन, बेटी की तरफ गलत नजर से देखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। समरस पंचायतों को अपने काम से पूरे देश में उदाहरण प्रस्तुत करना है। जनता की सेवा, गाँव का विकास, आँगनवाड़ी, स्कूल, पंचायत, सामुदायिक भवन का व्यवस्थित और परिणाममूलक संचालन हमारी प्राथमिकता हो। हम यह सुनिश्चित करें कि हमारी पंचायत में कोई बच्चा कुपोषित नहीं रहे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मुख्यमंत्री निवास परिसर में निर्विरोध निर्वाचन द्वारा समरस पंचायतों का गठन करने वाले प्रतिनिधियों के अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों को निर्विरोध निर्वाचित करने वाले ग्रामवासियों का आभार माना। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नारी सशक्तिकरण को समर्पित गीत की ध्वनि के साथ दीप प्रज्ज्वलन तथा कन्या-पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री निवास आये पंचायत प्रतिनिधियों का मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, सांसद श्री रमाकांत भार्गव, पूर्व मंत्री श्री रामकृष्ण कुसमरिया, विधायक श्री सीताराम आदिवासी सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में सरपंचों द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान का अभिनंदन किया गया। नर्मदापुरम जिले की तहसील बनखेड़ी की ग्राम पंचायत उमरधा की निर्विरोध निर्वाचित सरपंच सुश्री जागृति सिंह जूदेव और सीहोर जिले के बुधनी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत चिपरी के निर्विरोध निर्वाचित सरपंच श्री अमित चौहान ने अपने अनुभव तथा ग्राम विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताएँ और कार्य-योजना प्रस्तुत की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 630 सरपंच, 157 जनपद पंचायत सदस्य और एक जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। किसी भी पंचायत में सरपंच का निर्वाचन निर्विरोध रूप से होने पर 5 लाख रूपए, सरपंच पद के लिए वर्तमान और पिछला निर्वाचन निरंतर निर्विरोध होने पर 7 लाख रूपए तथा सभी पंच और सरपंच निर्विरोध निर्वाचित होने पर 7 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार पंचायत में सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन होने पर पंचायत को 12 लाख रूपए और पंचायत में सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध होने पर पंचायत को 15 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश में ही पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। महिलाओं में नेतृत्व क्षमता के साथ कर्मठता की कोई कमी नहीं है। इंदौर ने महिला महापौर के नेतृत्व में स्वच्छता के क्षेत्र में देश में कीर्तिमान स्थापित किया है। ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधि जनता की सेवा और गाँव के विकास में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि समरस पंचायतों को अपनी प्राथमिकता तय कर कार्य करना होगा। हम यह प्रण लें कि गाँव में कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं होगा। यदि कोई विवाद होता है तो उसे बातचीत से सुलझाया जाएगा, जिससे हम अपना समय और पैसा कोर्ट-कचहरी में बर्बाद नहीं होने देंगे। साथ ही यह भी हमारी प्राथमिकता हो कि केन्द्र और राज्य की सभी योजनाओं का लाभ पंचायत के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाए। ग्राम पंचायत में सभी लोग मिल-बैठकर अगले पाँच साल की विकास की कार्य-योजना तय करें और उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत में स्वच्छता, वृक्षारोपण, बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना, दिव्यांगों का सर्वे कर उन्हें संबंधित योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना, मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराना, गाँव को नशा मुक्त करना, गाँव में असामाजिक तत्वों और अवैधानिक गतिविधियों को न होने देना प्राथमिकता में शामिल किया जाए।

किसानों की लागत डूबी - हीट वेव से मेंथा में 60-70 फीसदी तक कम निकला तेल

मेंथा वर्ष 2022 की मार्च-अप्रैल के रिकॉर्ड तोड़ तापमान के चलते सिर्फ गेहूं के उत्पादन में ही 20 फीसदी से ज्यादा की गिरावट नहीं है बल्कि मेंथा समेत दूसरी फसलों का भी उत्पादन काफी कम हुआ है। किसानों के मुताबिक, फसल में पौधे पनप ही नहीं पाए, ज्यादा टहनियां और पत्ते नहीं हुए तो तेल भी कम निकल रहा है। उत्तर प्रदेश में मेंथा के गढ़ बाराबंकी के किसान गुड्डू के लिए ये सीजन काफी नुकसानदायक रहा है। गुड्डू के मुताबिक, पिछले साल जिस खेत में 30 किलो तेल निकला था वहां इस साल सिर्फ 8-9 किलो ही हुआ है। गुड्डू कहते हैं, ÷इस बार सब घाटा ही हुआ है। डीजल बहुत महंगा है। पैसा ज्यादा लगा है, पैदावार हुई नहीं। इस बार तो खर्चा भी ज्यादा हुआ है।

पिछले साल मई के अंत और जून के पहले हफ्ते की बारिश में करीब 70 फीसदी मेंथा चली गई थी और इस बार बिना बारिश के खराब हुई है। तपन (गर्मी) इतनी ज्यादा थी, फसल में ग्रोथ ही नहीं हुई। गर्मी का आलम ये था कि मेंथा में वैसे तो 9-10 दिन में पानी लगाना (सिंचाई) होता था, लेकिन इस बार कई जगहों पर 4 दिन में लगाना पड़ा। पुरवा हवा चलने से कीट भी बहुत लगे तो खेती में खर्चा बढ़ा, लेकिन उत्पादन कम हो गया। बरेली जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर आंवला के प्रगतिशील मेंथा किसान निहाल सिंह जैविक तरीके से मेंथा की खेती करते हैं, उनके साथ कई हजार किसान भी जुड़े हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बागवानी फसलों को लेकर अग्रिम अनुमान के मुताबिक, देश में साल 2021-22 में 336 हजार हेक्टेयर मिंट (मेंथा) की खेती हुई थी जिससे 39 मीट्रिक टन उत्पादन अनुमानित था, साल 2020-21 में 347 हजार हेक्टेयर से 46 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। लखनऊ स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के संस्थान केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौध संस्थान (सीमैप)के मुताबिक देश में कुल उत्पादन में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी यूपी की है। यूपी में मेंथा का औसत रकबा 2,75,000 हेक्टेयर है। यूपी के अलावा पंजाब, बिहार और हरियाणा में भी मेंथा की खेती का रकबा बढ़ रहा है, ये वही राज्य हैं जहां

मार्च-अप्रैल में भीषण गर्मी पड़ी है। वहीं, यूपी की बात करें तो इसके कुल उत्पादन का लगभग एक तिहाई हिस्सा बाराबंकी में होता है। बाराबंकी में 2021-22 में करीब 62 हजार हेक्टेयर में मेंथा की खेती हुई थी, वहीं उत्पादन के मामले में करीब 33 फीसदी हिस्सेदारी है। सीमैप के मेंथा विशेषज्ञ और प्रधान वैज्ञानिक डॉ. सौदान सिंह डाउन टू अर्थ को बताते हैं, ÷जो तापमान अप्रैल में होना था वो मार्च में ही हो गया था। इसलिए पौधा तैयार नहीं हुआ। वो गर्मी सहने के अनुकूल नहीं हो पाया था। इसलिए किसानों का नुकसान हुआ है। अपनी बात को समझाते हुए वो आगे बताते हैं, ÷जब मेंथा की प्लांटनिंग शुरुआती स्टेज में होती है और उसे फेयर टेंपरेंचर (अनुकूल मौसम) मिलता है, जैसे की फरवरी... तो पौधे की बढ़वार और विकास अच्छा होता है। लेकिन शुरू से अगर तापमान ज्यादा हुआ तो विकास नहीं हो पाता है। फरवरी में जो मेंथा लगाई जाती है उसकी हाइट 80 फीसदी तक जाती है, जबकि मार्च वाली की 60 फीसदी और अप्रैल में लगाई गई मेंथा 40 फीसदी ही ग्रोथ कर पाती है। मेंथा की रोपाई फरवरी से मई तक होती है, लेकिन अनुकूल मौसम फरवरी वाला ही होता है। मेंथा की खेती के लिए अनुकूल तापमान 20 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि मेंथा का तेल उसकी पत्तियों में होता है, इसलिए पौधे में ज्यादा कल्ले और पत्तियां जरूरी होती हैं। लेकिन इस बार तापमान मेंथा के लिए अनुकूल नहीं रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक मार्च 2022 में औसत तापमान (33.10 डिग्री सेल्सियस) था जो पिछले 122 वर्षों में सबसे ज्यादा था। हीट वेव का कहर साल 2010 में हुआ था, लेकिन इतना नहीं था। बाराबंकी जिले में ही तुरकौली गांव के किसान शैलेंद्र कुमार कहते हैं, ÷ये मेरा खेत है, 16-17 बीघा (लगभग सवा तीन एकड़) का जिसमें मेंथा लगा रखी थी, इनती मेहनत, खाद और दवा डालने के बाद भी पूरे खेत में सिर्फ एक ब्यॉयल (पेराई टंकी) लांक (फसल) निकली, जिसमें 13 किलो तेल मिला। जबकि पिछले साल इसी खेत में पौने 2 कुंटल तेल निकला था। लेकिन इस बार पौधे ही नहीं बढ़े, कल्ले नहीं निकले तो सब खराब हो गया। अपने खेत के एक कोने में लगे डीजल पंपिंग सेट की तरफ इशारा करते हुए वो कहते हैं, ÷20 हजार की दवा (पेस्टीसाइड) डाले हैं। जितना तेल हुआ है इससे तो डीजल का पैसा भी वापस नहीं आएगा। 3,600 रुपए कटाई और 1,300 रुपए पेराई दी है। मेरा कम से कम 50 हजार का घाटा है। लगातार हो रहे घाटे और मौसम की मार से परेशान बाराबंकी के एक अन्य किसान मो. शगीर कहते हैं, ऐसा ही रहा तो खेती छोड़नी पड़ेगी। 90 रुपए लीटर का डीजल लेकर इस बार पिपरमिंट में 12 सिंचाई किए थे, और तेल निकल रहा है 2-3 किलो बिगहा (एक एकड़-5 बीघा), ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मौसम बहुत गर्म था, बारिश हुई नहीं और फसल तैयार हो गई तो जो खेत में था उसकी पेराई करनी पड़ी। किसान और वैज्ञानिक दोनों के मुताबिक ज्यादा घाटा उन्हें हुआ जिन्होंने मार्च में रोपाई की थी, क्योंकि फरवरी में पौध रोपने वालों को मौका मिल गया था, उनका तेल भी अच्छा हुआ क्योंकि बाद में बारिश नहीं हुई तो पौधे पूरे तनाव में रहे, मिट्टी भी सूखी थी तो तेल अच्छा गिरा। लेकिन ऐसा करने वाले किसानों की संख्या सिर्फ 25-30 फीसदी बताई जाती है। ज्यादातर किसान सरसों काटकर, आलू खोदकर या फिर गेहूं काटकर मेंथा लगाते हैं, यानि रबी और खरीफ के बीच के समय में एक फसल लेते थे, ऐसे करीब 70 फीसदी किसान होते हैं, जिनका नुकसान हुआ है। सौदान सिंह आखिर में कहते हैं, यहां तापमान से ज्यादा अहम तकनीकी है, कि आपने मेंथा की रोपाई कब और कैसे की। बदलती जलवायु को देखते हुए अगर आप देर से रोपाई करते हैं तो पौधे से पौधे की बीच की दूरी घटा दें। दूसरा इस बार भी देखेंगे तो जिन किसानों ने मेड़ के ऊपर मेंथा लगाई थी, उनका उत्पादन अच्छा हुआ है।÷

जलवायु संकट-मध्य एशिया के मैदानी इलाके गर्म और शुष्क रेगिस्तान में बदल रहे हैं, पहाड़ों पर बढ़ी बारिश

मुंबई।मध्य एशिया की 60 फीसदी से अधिक हिस्सों की जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क है। ऐसी जलवायु में फसल पैदा करने और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर जलवायु की विविधताओं का विशेष रूप से असर पड़ता है।यहां तक कि मामूली सूखे वाले सालों में भी कृषि उपज का काफी नुकसान होता है। जिसके कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है और देशों के वित्त और सामाजिक स्थिरता को खतरा होता है।

इस प्रकार यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र में जलवायु कैसे बदल रही रही है और यह परिवर्तन इस क्षेत्र को किस दिशा में ले जा रहा है शोधकर्ताओं की एक टीम ने ग्लोबल वार्मिंग के तहत बदलती परिस्थितियों के बारे में अधिक जानने के लिए मध्य एशिया में मौसम का क्षेत्र-दर-क्षेत्र अध्ययन किया। अध्ययन में क्यूई हू और जिहांग हान ने वर्णन किया है कि कैसे उन्होंने इलाकों पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के बारे में अधिक स्थानीय आधार पर जानकारी हासिल करने के लिए इस क्षेत्र को अलग-अलग हिस्सों में विभाजित किया। यह अध्ययन नेब्रास्का विश्वविद्यालय के प्राकृतिक संसाधन स्कूल और पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। जैसे-जैसे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है, दुनिया भर के वैज्ञानिक यह समझने के लिए हाथ-पांव मार रहे हैं कि एक गर्म होती दुनिया कैसी दिखेगी। इस नए प्रयास में, हू और हान ने अध्ययन को मध्य एशिया पर केंद्रित किया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और चीन के कुछ पश्चिमी हिस्से जैसे देश शामिल हैं।

मध्य एशिया का अधिकांश भाग शुष्क है और इसका अधिकतर भाग रेगिस्तानी है। शोध से पता चला है कि जैसे-जैसे क्षेत्र गर्म हो रहा है, यह भी सूखता जा रहा है, अध्ययन में बताया गया है कि इस क्षेत्र के कुछ हिस्से अंततः निर्जन हो जाएंगे। इस नए प्रयास में, शोधकर्ताओं ने गौर किया कि मध्य एशिया में जलवायु परिवर्तन में अधिकांश शोधों ने पूरे क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है, जो कि स्थानीय जलवायु में हो रहे बदलावों को कम करने के प्रयासों में योगदान नहीं करता है। उस स्थिति को सुधारने के लिए, उन्होंने इस क्षेत्र को 11 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। उनमें से प्रत्येक के लिए जलवायु के आंकड़ों का अध्ययन किया ताकि यह देखा जा सके कि अब तक क्या-क्या बदलाव हो चुके हैं और यदि संभव हो तो भविष्य में होने वाले बदलावों का पूर्वानुमना लगाने के लिए ऐसा किया गया। स्थानीय आधार पर क्षेत्रों को देखते हुए, शोधकर्ताओं ने पाया कि हवा के तापमान में 1990 से 2020 के बीच औसतन 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो गई है। उन्होंने यह भी पाया कि रेगिस्तानी इलाके बढ़ रहे हैं, उत्तर और पूर्व दोनों जगहों पर इनका विस्तार हो रहा है। 1980 के दशक के मध्य से मध्य एशिया के कई इलाकों में रेगिस्तान उत्तर की ओर 100 किमी से अधिक का विस्तार हुआ है। रेगिस्तान में बदलने वाले अधिकांश क्षेत्रों में बारिश कम हो रही है। शोधकर्ताओं को कुछ पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में भी अधिक वर्षा होने का पता चला है, लेकिन यह बर्फबारी के बजाय अधिक बार बारिश हुई है।

सभी आर्थिक निर्णयों में पर्यावरण पहलू को शामिल करने को तंत्र बनाने की जरूरत – विशेषज्ञ

नयी दिल्ली देश में सभी आर्थिक निर्णयों में पर्यावरण के पहलू पर प्रणालीगत तरीके से विचार को एक तंत्र स्थापित करने की जरूरत है। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा मंगलवार को 'सतत विकास के लिए डाटा- भारत का पर्यावरण खाता और नीति तथा निर्णय प्रक्रिया में इसकी भूमिका' विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए विशेषज्ञों ने यह बात कही।

ऐमजॉन पर फोन फेस्ट, 30 जून तक मोबाइल फोन्स पर बंपर ऑफर्स मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि संगोष्ठी में इस बात पर जोर दिया गया कि विशेषरूप से भारत जैसे विकासशील देशों को सभी आर्थिक निर्णयों में पर्यावरण के प्रणालीगत पहलू पर विचार के लिए तंत्र स्थापित करने की जरूरत है। मंत्रालय ने इस संगोष्ठी का आयोजन नीति में पर्यावरण को एक प्रमुख पहलू में शामिल करने के उद्देश्य से किया था। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव जी पी सामंत ने पर्यावरण खातों के क्षेत्र में मंत्रालय की पहल के बारे में जानकारी दी। संगोष्ठी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए मंत्रालय द्वारा शुरुआती चरण में ही पर्यावरण खातों को अपनाने की सराहना की।

पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक, अन्यथा नहीं मिलेगी प्राणवायु

प्रतापगढ़. जिले के जंगलों में गत वर्षों से अवैध गतिविधियां बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही वन क्षेत्र से अवैध दोहन भी हो रहा है। जिसमें पेड़ों की कटाई प्रमुख है। इसके साथ ही गत वर्षों से वन्यजीवों के शिकार के मामले भी देख जा रहे है। हालांकि वन विभाग की ओर से गश्त की जा रही है। लेकिन अवैध गतिविधियों में कमी नहीं हो रही है। ऐसे में वन विभाग की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है। आगे के लिए विभाग की ओर से जो योजना बनाकर अमल में लाई जाएगी। इसे लेकर पत्रिका की ओर से उपवन संरक्षक सुनील कुमार से बातचीत की गई। इसके प्रमुख अंश इस प्रकार हैं।

गत वर्षों से जंगल में हरियाली में कमी आई है, इसके कई कारण है। जिसमें अवैध कटाई तो है ही। गत वर्षों से वनाधिकार अधिनियम की आड़ में कुछ लोग लालच में अपने खेत की सीमा बढ़ाने के लिए पेड़-पौधे आदि की कटाई कर जमीन पर कब्जा करते है। इसके साथ ही कई बार जंगल में निवासरत लोगों को बाहर के माफिया आकर लालच में जंगल कटवाते है। ऐसे में जंगल क्षेत्र में हरियाली में कमी आ रही है। ऐसे में हमें अभी से चेतना होगा, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण करना होगा। अन्यथा प्राणवायु की भी दिक्कत हो सकती है। जंगल में वन्यजीवों की संख्या में कमी होने का प्रमुख कारण जंगल में मनुष्यों की गतिविधियां बढना है। गत वर्षों से पर्यावरण संतुलन बिगड़ता जा रहा है। जिसमें जंगल में वन्यजीवों की संख्या कम होती जा रही है। वहीं मनुष्य अब जंगल में घुसपैठ करने लगे है। ऐसे में कई प्रजातियों के वन्यजीव अपना प्राकृतिक आवास छोडने के लिए मजबूर हो जाते है। जिससे इनकी संख्या में कमी आने लगी है। कुल मिलाकर प्राकृतिक संतुलन बिगडने से इसका सीधा असर हो रहा है।

वन विभाग की ओर से प्रति वर्ष पौधे लगाए जाते है। जो बारिश होने के एक माह बाद लगाए जाते है। ऐसे में कई पौधे बारिश में ही खत्म हो जाते है। इसमें कुछ पौधों को मवेशी नुकसान पहुंचा देते है। जबकि कुछ पौधे बारिश खत्म होने के बाद पानी नहीं मिलने से जीवित नहीं रह पाते है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए इस बार से बारिश से पहले ही बीजारोपण शुरू किया गया है। जिसमें पेड़ की प्रजातियों के अनुसार नालों के किनारे, ऊंचाई पर और ढलान में बीजारोपण किया जा रहा है। जिससे बारिश होने पर यह अंकुरित हो जाएंगे। इससे आगामी तीन माह तक पानी मिलेगा। जिससे इन पौधों की लंबाई भी अपेक्षाकृत अधिक हो जाएगी। वहीं जो पौधे तैयार किए गए है। वह भी पहली बारिश के बाद ही पौधरोपण किया जा रहा है। जिससे अधिक मात्रा में पौधे जीवित रह सके।

जंगल से मिट्टी दोहन के मामले एक दशक से बढ़े है। इसके तहत अधिकांश मामले में ईंट-भट्टों में ही इसका उपयोग होना सामने आया है। मिट्टी के दोहन पर अंकुश लगाने के लिए विभाग की ओर से लगातार गश्त की जा रही है। इस वर्ष से विभाग की ओर से जो भी ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी है। उसे राजसात किया जा रहा है। जिससे मिट्टी दोहन पर अंकुश लगा है। हालांकि कुछ स्थानों पर चोरी-छुपे इस प्रकार की गतिविधियां जारी है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे है। यह समस्या गत कई वर्षों से चली आ रही है। जंगल में आदिवासियों के कब्जे को लेकर सरकार की ओर से वनाधिकार के तहत पट्टे दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जिसमें जिन लागों के जंगल में वर्ष 2005 से पहले का कब्जा होता है। उसे ही वनाधिकार दिया जा रहा है। हालांकि कई लोग इसकी आड़ में जंगल में पेड़-पौधों की कटाई कर कब्जा बताते है। जबकि विभाग की ओर से इसके लिए गत वर्षों का जीपीएस और गुगल मेप के आधार पर जांच की जाती है। जिसमें कब्जा किस वर्ष का है, यह स्पष्ट पता चल जाता है। जिससे इस प्रकार के दावे खारिज हो जाते है। कब्जों के लिए विभाग और सरकार की ओर से गुगल मेप और जीपीएस की रिपोर्ट प्रमुख रूप से मान्य होती है। इससे लोगों को इस संबंध में भी जानकारी दी जा रही है।गश्त कर मनुष्यों और सभी जीवों के अस्तित्व के लिए पर्यावरण का अहम् योगदान है। यह तो हम सभी जानते है। गत वर्षों से प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके परिणाम भी सामने आने लगे है। ऐसे में आमजन से यही अपील है कि वे पर्यावरण संतुलन में योगदान दें। पर्यावरण में नुकसान नहीं पहुंचाए। अधिक से अधिक मात्रा में पेड़-पौधे लगाकर संरक्षण करें। जंगल बचाने के लिए वन विभाग की मदद करें। कोई भी व्यक्ति अगर जंगल का नुकसान करता दिखे तो उसे रोके और इनका हमारे जीवन पर पडने वाले असर की जानकारी दें।

ग्राम वन समिति वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिये प्रस्तुत कर रही हैं अनूठी मिसाल

इन्दौर राज्य शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार इंदौर जिले में वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिये गठित की गई ग्राम वन समितियां बेहतर कार्य कर रही है। अनेक ऐसी समितियां है जिन्होंने वनों को बढ़ाने और वनों की सुरक्षा के लिये अनूठी मिसाले प्रस्तुत की हैं। इन्हीं में शामिल है जिले की ग्राम वन समिति शिवनी तथा वन समिति नाहर झाबुआ।

वन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्री ए.के. श्रीवास्तव ने बताया कि इंदौर जिले में कुल 116 ग्राम वन समितियां वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये लगातार कार्य कर रही हैं। इन समितियों के माध्यम से वनों की सुरक्षा और वन क्षेत्र बढ़ाने में मदद भी मिल रही है। उन्होंने बताया कि इंदौर जिले की ग्राम वन समिति शिवनी (गढ़ी) ने वन क्षेत्र बढ़ाने में बेहतर सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने बताया कि गढ़ी क्षेत्र में लगभग साढ़े 26 हेक्टेयर में 32 हजार 150 पौधे लगायें। वन समितियों की लगातार देखभाल से पौधों को जीवित रखने और उन्हें बढ़ाने में मदद मिल रही है। इसके फलस्वरूप लगाये गये 32 हजार 150 पौधों में से लगभग 26 हजार पौधे पूर्ण रूप से जीवित और सुरक्षित हैं। इस तरह पौधों के जीवित रहने का प्रतिशत 80 से अधिक है। यह उपलब्धि बेहतर मानी जाती है। पौधों को जीवित रखने में और उनकी देखभाल और सुरक्षा के लिये वन समिति के अध्यक्ष श्री सलीम अकरम पटेल द्वारा उल्लेखनीय सहयोग दिया जा रही है। वे अपने 40 सदस्यों के साथ में लगाये गये पौधों की लगातार देखभाल कर रहे हैं। वन विभाग के अमले को पूरा सहयोग उनके द्वारा दिया जा रहा है। इसी तरह वन क्षेत्र की बढ़ोत्तरी के लिये नाहर झाबुआ की वन समिति द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि इस क्षेत्र में दो हजार के अधिक हेक्टेयर का वन क्षेत्र है। आज से दस वर्ष पूर्व बड़ी संख्या में वन को नुकसान पहुंचता था। वनों की अवैध कटाई होती थी। उस वक्त दस से 15 प्रकरण हर माह अवैध कटाई के दर्ज होते थे। वन विभाग के अमले द्वारा वन समिति को सक्रिय किया गया। 35 ग्रामीणों को लेकर वन समिति बनाई गई। इनका बेहतर सहयोग मिलने लगा। इस समिति के वर्तमान में श्री रूप सिंह बानिया अध्यक्ष हैं। बताया गया कि वन समिति के सक्रिय सहयोग से प्रकरणों में साल दर साल कमी आती गई। वर्तमान में माह में अब एक या दो ही छोटे-छोटे प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। वन समितियों का सहयोग बेहद मददगार साबित हो रहा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008